भारतीय संविधान से जुड़े नियमों का महत्त्व क्या है?

'Rules of the Game (रूल्स ऑफ़ दी गेम)' – भारतीय संवैधानिक विधि में उत्पन्न होने वाली हालिया घटनाओं का वर्णन करती एक श्रृंखला

क्यों आवश्यक है खेल में नियम?

किसी भी खेल, मान लीजिये क्रिकेट, की कल्पना करिये। क्रिकेट के हर संस्करण में खिलाड़ी हमेशा २ टीमों में बटे होते हैं, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट या टी-२०। खिलाड़ी अपने कौशल, रणनीति एवं धैर्य के बल पर प्रतिद्वंदी टीम को पराजित करते हैं। परन्तु वे जीतना क्या चाहते हैं? और कैसे? यह जाहिर सी बात है कि नियमों के अभाव में किसी भी खेल को खेलना या जीतना संभव नहीं है। प्रथम टीम को दूसरी टीम से अधिक रन जोड़ने हैं, या फिर दूसरी टीम को जल्दी से आउट करने का प्रयास करना है - क्या इस जानकारी के बगैर क्रिकेट खेलना मुमकिन है? बुनियादी नियमों के अभाव में क्रिकेट का अस्तित्व ही क्या है? चाहे क्रिकेट हो या मुक्केबाज़ी, कोई भी खेल प्रतिद्वंदियों के बीच केवल एक संग्राम नहीं है।

राजनीति में क्यों आवश्यक है नियम?

बीते कुछ वर्षो में उत्पन्न हुए कुछ राजनीतिक विवादों पर विचार करते हैं:

- २०१९ में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून पर जहां आलोचकों ने इसे धर्म के आधार पर भेदभाव करने को मुद्दा बनाकर ख़त्म करने की मांग की है, वहीँ इस क़ानून के समर्थकों का यह तर्क था कि भारत का संविधान कुछ स्थितिओं में पहले से ही ऐसे भेदभाव की अनुमति देता है।
- राजनीतिक दलों को उचित रूप से चंदा उपलब्ध कराने एवं चंदा देने वालों को किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए चुनावी-बॉन्ड-योजना का प्रस्ताव रखा गया। चुनावी बॉन्ड के ये लाभ होने के बावजूद, यह कहना कठिन है के चुनाव जीतने के बाद, राजनीतिज्ञ अपने चुनाव क्षेत्र से अधिक चंदा देने वालों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे।
- जम्मू और कश्मीर जैसे कुछ राज्यों के प्रतिनिधि कुछ शर्तों के आधार पर ही भारतीय संघ में शामिल हुए थे। ऐसे में अगर भविष्य में परिस्थिति में बदलाव के कारण इन शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो संविधान में ऐसी और शर्तों की विश्वसनीयता कम हो सकती है।

यह ३ मुद्दे भारतीय राजनीती से जुड़े कुछ उदाहरण हैं। ऐसे मामलों में जनता की राय, उनके अपने व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव के आधार पर बंट जाती है। फलस्वरूप ऐसा लग सकता है कि यह मुद्दे केवल राजनीतिक प्रतिद्वदियों के बीच उठने वाले सामान्य टकराव के मुद्दे हैं। वास्तविकता में

यह संविधान और उससे जुड़े नियम व कानून से सम्बंधित विषय हैं। प्रतिदिन टीवी न्यूज़ चैनलों व इंटरनेट पर होने वाले वाद-विवाद और शोरगुल में इस तथ्य को भूल जाना स्वाभाविक है।

वर्त्तमान समय में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि राजनीति नियम-कानून से परे है, जहाँ केवल व्यक्तिगत हित एवं विजय प्राप्त करने का महत्त्व है। पर क्या यह सही है? कल्पना करिये एक ऐसे भारत देश का जहां शासन और राजनीति बिना किसी नियम-कानून के चल रहे हों। शासन से सम्बंधित मुद्दों या विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा? क्या नागरिकों के प्रति सरकार का कोई दायित्व और ज़िम्मेदारी नहीं होगी? चुनावों का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा? शासन विधि और राजनीति से सम्बंधित इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए जो नियम-क़ानून तय होते हैं वह भारत के संविधान के अनुरूप बनाये जाते हैं। अतः संविधान केवल वकीलों और न्यायाधीशों के उपयोग हेतु नहीं बनाये जाते बल्कि यह शासन और राजनीति को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं। क्रिकेट की तरह, शासन विधि और राजनीति भी केवल प्रतिद्वंदियों के बीच सिर्फ एक संग्राम नहीं है।

<u>राजनीतिक खेल का महत्त्व क्या है?</u>

क्रिकेट के खिलाडियों की ही तरह, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी कुछ बुनियादी नियमों की जानकारी निश्चित होनी चाहिए। राजनीति में यह बुनियादी नियम संविधान तय करते हैं।

किसी भी संविधान का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रावधानों को वास्तव में कितनी अच्छी तरह से समझा जा रहा है। भले ही संवैधानिक सिद्धांतों को एक आम नागरिक अच्छे से न समझे, जनता के बीच संविधान के प्रति सम्मान और विश्वास हमेशा से देखने को मिला है। परन्तु संवैधानिक कानून से उत्पन्न होने वाली असहमतियों के निवारण हेतु यह जानना आवश्यक है कि मूल रूप से संविधान क्या कहता है अथवा किन मूल्यों की वह रक्षा करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव को कब अनुमति मिल सकती है? चुनाव के पूर्व मतदाता को क्या-क्या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है? संविधान के प्रावधानों का संशोधन किस प्रकार और किन परिस्थितिओं में किया जा सकता है? इन विषयों के सन्दर्भ में चुने गए संवैधानिक विकल्पों का परिणाम केवल आज या कल नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षो के लिए महत्त्वपूर्ण होता है।

वर्त्तमान समय में अनेक राजनीतिक विवादों से हमारा सामना हो रहा है। जिस प्रकार क्रिकेट अनेक प्रकार से खेला जा सकते है (जैसे टेस्ट, वनडे, टी-२०), उसी प्रकार से हमारी सरकार एवं न्यायालय हमें संविधान के विभिन्न संस्करणों की ओर ले जा सकते हैं। हम संविधान के किस संस्करण की ओर जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम संविधान से क्या उम्मीद रखते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी सरकार प्रभावी रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे? क्या हम चाहते हैं कि हमारी

सरकार अत्यंत रूप से केंद्र शासित रहे या फिर एक ही पार्टी द्वारा चलाया जाये? या फिर जातीय राष्ट्रवाद की ओर बढ़े? यह सब मुमकिन तब है जब राजनीति के खेल के नियम ही बदल दिए जाएँ।

परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है - क्या हम चाहते हैं कि राजनीति का खेल निष्पक्ष रहे? क्या हम क्रिकेट निष्पक्षता के बगैर खेलना पसंद करेंगे?

अपने पाठकों को समकालीन राजनीतिक घटनाओं से सम्बंधित एक विस्तृत दृष्टिकोण देने के लिए हम 'Rules of the Game (रूल्स ऑफ़ दी गेम)' नामक श्रृंखला आरम्भ कर रहे हैं। इस शृंखला के अंतर्गत नियमित ब्लॉग लेखों (blog posts) के माध्यम से उन घटनाओं की व्याख्या की जाएगी जिनका प्रभाव संविधान एवं उससे जुड़े नियमों पर पड़ता है।